|  |  |
| --- | --- |
| **(क)** | क्‍या यह सच है कि अक्‍तूबर, 2011 में महंगाई 6 महीने के उच्‍चतम स्‍तर पर पहुंच गई थी; |
| **(ख)** | यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और  |
| **(ग)** | पिछले एक वर्ष के दौरान महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों का उपलब्‍धि सहित ब्‍यौरा क्‍या है? |

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)**

**(क) और (ख):** थोक मूल्‍य सूचकांक (डब्‍ल्‍यूपीआई) के संदर्भ में वर्षानुवर्ष हेडलाइन मुद्रास्‍फीति पिछले छह महीनों (अप्रैल-सितम्‍बर, 2011) के 9.61 प्रतिशत के औसत मुद्रास्‍फीति की तुलना में अक्‍तूबर, 2011 में 9.73 प्रतिशत थी। अप्रैल, 2011 से अक्‍तूबर, 2011 तक की माह-वार हेडलाइन डब्‍ल्‍यूपीआई मुद्रास्‍फीति की दरें नीचे सारणी में दी गई हैं:-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अप्रैल, 11 | मई- 11 | जून -11 | जुलाई-11  | अगस्‍त-11 | सितम्‍बर 11 | अक्‍तूबर 11 |
| 9.74 | 9.56 | 9.51 | 9.36 | 9.78 | 9.72 | 9.73 |

**(ग):** आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं: चावल, दालों, खाद्य तेलों (कच्‍चा) पर आयात शुल्‍क शून्‍य कर दिया गया, खाद्य तेलों (नारियल के तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (प्रति वर्ष अधिकतम 10,000 टन की मात्रा तक काबुली चना और जैव दालों को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध, वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, उड़द तथा तूर के वायदा कारोबार को आस्‍थगित किया गया, दालों, धान और चावल के मामले में स्‍टॉक सीमा संबंधी आदेशों को बढ़ाकर 30 सितम्‍बर, 2011 तक किया गया, वित्‍त वर्ष में कुल 10,000 मीट्रिक टन तक आयात करने के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्‍यू) के तहत स्‍किम्‍ड मिल्‍क पाउडर (एसएमपी) का शुल्‍क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया, टीआरक्‍यू के तहत 2010-11 के दौरान राष्‍ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को शून्‍य शुल्‍क पर 30,000 टन दूध पाउडर और 15,000 टन दुग्‍ध वसा के आयात की अनुमति दी गई, कच्‍चे तेल पर सीमा शुल्‍क तथा पेट्रोल और डीजल पर आयात शुल्‍क में कटौती की गई।

मौद्रिक नीति की समीक्षा के कार्य के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्‍यवस्‍था की क्षमता के अनुरूप मांग के स्‍तर को संतुलित करने के लिए पॉलिसी दरों में लगातार 13 बार वृद्धि करने के साथ-साथ संबंधित उपाय करने हेतु उचित कदम उठाए हैं ताकि कीमतें बढ़ने दिए बिना अर्थव्‍यवस्‍था के विकास की रफ्तार बनाए रखी जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक की 25 अक्‍तूबर, 2011 की हाल ही की घोषणा के अनुसार, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को संशोधित करके क्रमश: 8.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

नीतिगत कार्रवाई के परिणामस्‍वरूप, हम मुख्‍यत: हेडलाइन डब्‍ल्‍यूपीआई मुद्रास्‍फीति पर काबू पाने और उसकी संभावनाएं कम करके दोहरे अंक के स्‍तर से नीचे रखने में सफल रहे हैं, हालांकि सरकार की निश्‍चित मंशा यह है कि इसे शीघ्र कम करके अधिक संतोषजनक स्‍तर पर लाया जा सके।

**\*\*\*\*\***